

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क/199/अ.प्र./पैथा-लैब/2006/

भोपाल दिनांक 29/4/2006

प्रति,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय : याचिका क्रमांक 3721/02 (श्रीमती कमला पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश दिनांक 13.01.03 का प्रदेश में क्रियान्वयन व अवमानना याचिका क्रमांक 1779/05 (डॉ. नाजपांडे विरुद्ध कोमल सिंह पैथालाजी लैब-विजिटिंग पैथालोजिस्ट बावत)

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के क्रमांक क/अ.प्र./पैथा-लैब/2005/624 दिनांक 20.09.2005 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के याचिका क्रमांक 3721/02 में पारित आदेश दिनांक 13/01/2003 के संदर्भ में ऐसी समस्त पैथालाजी प्रयोगशालाएं जो योग्यताधारी विजिटिंग पैथालोजिस्ट की सेवाएं लेकर चलाई जा रही हैं के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा विजिटिंग पैथालोजिस्ट के रोल पर दिये गये अभिमत के परिपेक्ष्य में निर्देश जारी किये गये थे।


विजिटिंग पैथालोजिस्ट के रोल पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13/01/03 में आदेश के पैरा 31 में विस्तृत चर्चा करते हुए निम्न अभिमत व्यक्त किया है :-

"..... The Pathologist must attend the laboratory regularly and should perform the reading and should get the test performed under his supervision and only thereafter can sign the reports. Same is necessary to weed out quackery from the field of Pathological Laboratories. The laboratories which are not being run by pathologist cannot be, in my opinion, allowed to run by state. Pathologist should run the laboratory on regular basis and must have the deep and real interest in running of laboratory In any case such laboratories in which pathologist is not on regular basis, cannot be allowed to run at all."

स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश के क्रमांक क/अ.प्र./पैथा-लैब/2005/624 दिनांक 20.09.2005 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के याचिका क्रमांक 3721/02 में पारित उक्त आदेश के संदर्भ में ऐसी समस्त पैथालाजी प्रयोगशालाएं जो योग्यताधारी विजिटिंग पैथालोजिस्ट की सेवाएं लेकर चलाई जा रही हैं के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु कई जिलों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक-एक योग्यताधारी पैथालोजिस्ट कई-कई पैथालाजी प्रयोगशालाओं (कुछ प्रकरणों में चार-चार/पांच-पांच) में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर मात्र कर रहे हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय की मंशा अनुसार प्रयोगशालाओं में जांचें उनके सुपरविजन में नहीं हो रही हैं।

चूंकि ये स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की मंशा के अनुरूप नहीं है अतः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक अ.प्र./पैथा-लैब/2005/624 दिनांक 20.09.05 में एतद् द्वारा संशोधन कर ये व्यवस्था दी जाती है कि अपनी स्वयं की प्रयोगशाला के अतिरिक्त योग्यताधारी पैथालोजिस्ट केवल एक अतिरिक्त प्रयोगशाला में विजिटिंग पैथालोजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं इस शर्त पर दे सकेंगे कि उक्त प्रयोगशाला में की जा रही समस्त जांचें उनके सीधे सुपरविजन में

की गई हैं जिसके किसी भी लीगल प्रकरण हेतु वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र वे जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शपथ पत्र में ये उल्लेख भी होना आवश्यक है कि वे अपनी प्रयोगशाला में तथा विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रूप में जिस पैथालाजी प्रयोगशाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे उस प्रयोगशाला में किस समय से किस समय तक उपस्थित रहेंगे तथा अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 13.01.02 की अवमानना मानते हुए तथा झूठा शपथ पत्र देने का प्रकरण हेतु विधिवत कार्यवाही की जा सकेगी। जो पैथालाजिस्ट अपनी स्वयं की प्रयोगशाला संचालित नहीं करते हैं वे विजिटिंग पैथालाजिस्ट के रूप में उपरोक्तानुसार अपनी सेवाएं दो प्रयोगशालाओं की सीमा तक ही देंगे।

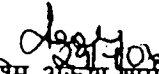

रश्मि अरुण शमी
स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.

पृ.क/200/अ.प्र./पेथा-लेब/2006/

भोपाल दिनांक 29/4/2006

प्रतिलिपि:

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


रश्मि अरुण शमी
स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र.